(b) and (c) The currently prescribed interest rate on Savings Deposits is considered appropriate taking into account the presently prevailing conditions in the economy. Interest rates are, however, under continuing review and changes are made therein taking into account emerging developments in the economy.

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य-निष्पादन

3288 **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध सिवाओं में मुख्य कमियां क्या हैं ;

(ग) क्या बैंक चैक बुक जारी करने के लिए सेवा प्रभार लगाने जा रहे हैं और यदि हां तो इसका सामान्य ग्राहकों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या यह भी सच है कि बैंक अन्य स्थानों के चैकों की भांति चैकों के निपटान के लिए भी सेवा प्रभार लगाने जा रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसका आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(च) बैंकों को अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद संस्थायें बनाने के लिए उनकी कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(छ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भांति राष्ट्रीयकृत बैंक भी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना आरम्भ करने जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर०बी०आई०) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकारी परिणामों में वित्तीय वर्ष 1992-93 की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान सुधार हुआ है। वर्ष 1994-95 के लिए बैंकों के वार्षिक लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ख) बैंकिंग प्रणाली के प्रति ग्राहकों की जागरुकता और उससे उनकी अपेक्षायें काफी बढ़ गई हैं। जब कभी सेवाओं में कमियां, यदि कोई हों, पाई जाती है तो सम्बद्ध बैंकों को गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार के लिये कहा जाता है ।

(ग) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) ने सूचित किया है कि बैंक, जुलाई, 1990 से ही मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकागनिशन (एम आई०सी०आर०) निकासी परिचालन वाले केन्द्रों पर एम.आई.सी.आर. चैक बुक जारी करते समय चालू खातों और गैर-व्यक्तिगत बचत खातों के लिये प्रति चैक पर्ची 1 रुपए प्रभार ले रहा है । तथापि अक्तूबर, नवम्बर, 1994 से आगे बैंकों ने उन व्यक्तिगत बचत बैंक खातों के लिये भी यह प्रभार निर्धारित किया है जिनमें एक वर्ष में 20 चैक पर्ची वाली तीन चैक बैंकों से अधिक का उपयोग होता है । एक वर्ष में बीन मुफ्त चैक बक से यह सुनिश्चित होगा कि उन व्यक्तियों/आम ग्राहकों पर कोई प्रभार नहीं लगा है जो सही बचत उद्देश्यों के लिए खाता परिचालित करते हैं, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं ।

(घ) भारतीय बैंक संघ के अनुसार स्थानीय चैकों के समाशोधन के लिये बैंकों ने कोई सेवा प्रभार लागू नहीं किया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) बैंक अपनी आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने और अनुपयोज्य आस्तियों में कमी करने के लिए कदम उठा रहे हैं । बैंकों द्वारा अपने व्यय को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध ढंग से कुल शाखाओं का स्वचलीकरण, लघु उद्योग, निर्यात, अनिवासी भारतीयों जैसे बैंक

ग्राहकों की श्रेणियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक विशेषज्ञ शाखायें खोलने के लिए कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। आशा की जाती है कि इन सबसे बैंक की कार्यक्षमता और लाभप्रदता में सुधार होगा।

(छ) भारतीय बैंक संघ के अनुसार फिलहाल प्रोत्साहन पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का कोई विचार नहीं है जैसाकि सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में प्रचलित है।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

Dharna by Regional Rural Bank Employees Association

3289. DR. BIPLAB DASGUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received a notice for massive Dharna at Delhi on 25th April, 1995 from All India Regional Rural Bank Employees' Association, if so, what are the issues raised; and

(b) what action has been taken by Government on the issues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) (a) Yes, Sir. The Association has raised broadly the following issues:—

(i) The formation of National Rural Bank of India by merging all Regional Rural Banks.

(ii) Release of one additional increment in terms of Government settlement with the Banking Industries on 29th October, 1993.

(iii) Publication of amendment of Recruitment-cum-Promotion Rules immediately.

(iv) Formation of Negotiating Forum.

(v) Immediate negotiation with IBA on VIth Bipertite settlement.

(b) As regard demand regarding formation of National Rural Bank of India (NRBI), it has been decided to restructure the Regional Rural Banks (RRBs) and 49 RRBs out of total of 196 RRBs were selected for comprehensive restructuring including cleansing of their blance sheets and infusion of fresh capital. As regard publication of amendment of Recruitment-cum-Promotion Rules, the matter is already under examination in consultation with Ministry of Law. The other demand needs further examination by the Government keeping in view the on-going restructuring of RRBs.

Pending issues of Regional Rural Banks

3290. DR. BIPLAB DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the issues relating to Regional Rural Bank staff benefit and service conditions pending with Government and the period of pendency;

(b) what are the issues relating to staff benefit and service matters of Regional Rural Bank staff that are pending with National Bank for Agriculture and Rural Development and the period of pendency: and

(c) what is the expected time for settlement of the above issues, issuewise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) (a) to (c) The issues raised are regarding the implementation of National Industrial Tribunal (NIT) Award and consequential changes in the salary structure of RRBs and abolition/merger of certain posts necessitating changes in the existing service regulations and other matters including recruitment and promotion policy. The Drafts of the Staff Services Regulations and Promotion Policy have been prepared in consultation with National Bank for Agriculture and Rural